



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2018/ वैशाख 21, 1940

No. 172]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2018/VAISAKHA 21, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

फा. सं. 19018/12/2015-ओएनजी-I.—दिनांक 19.07.1997 की कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति अधिसूचना संख्या ओ-12011/1/97/ओएनजी.डीओ.IV में आंशिक संशोधन करते हुए और दिनांक 03 नवंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 19018/12/2015-ओएनजी-I के अधिक्रमण में भारत सरकार तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारित क्षेत्रों, जिनके लिए उनके पास कोयला हेतु खनन पट्टा है, में अन्वेषण और दोहन के अधिकार प्रदान करने के लिए समेकित निबंधन और शर्तों को निम्नानुसार एतद्वारा अधिसूचित करती है :-

- i. कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 अथवा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम अथवा कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 अथवा यथा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिनियम के तहत सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के पास कोयले के उत्खनन हेतु निहित अधिकार/खनन पट्टे को पीएनजी नियम 1959 के तहत सीबीएम के अन्वेषण और दोहन के लिए प्रदान किया गया खनन पट्टा माना जाएगा। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को ऐसे क्षेत्रों के लिए सीबीएम के उत्खनन हेतु पीएनजी नियम 1959 के तहत अलग से लाइसेंस/पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
- ii. पट्टाधारक के रूप में सीआईएल और उसके सहायक कंपनियां ऐसे सभी ब्लॉकों/क्षेत्रों में सीबीएम प्रचालनों के लिए ओआरडी अधिनियम 1948 और पीएंडएनजी नियम 1959 का अनुपलान करेंगी।

- iii. पट्टाधारक प्राकृतिक गैस के उपयोग और मूल्य निर्धारण के लिए भारत सरकार की मौजूदा नीति का अनुपालन करेंगे।
- iv. पट्टाधारकों द्वारा राज्य/केंद्र सरकार को समय-समय पर यथालागू रॉयल्टी तथा अपेक्षित शुल्कों, उगाहियों और करों का भुगतान प्राकृतिक गैस के लिए किए जाने वाले अपेक्षित भुगतानों के समान प्रचलित दरों और समय-समय पर यथासंशोधित दरों पर किया जाना अपेक्षित होगा।
- v. सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार को कूप शीर्ष पर 10 प्रतिशत यथा बिक्री मूल्य की दर से रॉयल्टी का भुगतान तथा केंद्र सरकार को सीबीएम संविदा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को भारतीय रुपए में 0.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्धारित एकबारगी सिग्नेचर बोनस का भुगतान तथा सीबीएम उत्पादन पर उत्पादित सीबीएम के बिक्री मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) किया जाना अपेक्षित होगा।
- vi. दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-कस्टम्स के क्रम संख्या 404, उसमें निहित अन्य संबंधित प्रावधानों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य अधिसूचनाओं के तहत आयातों पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट लागू होगी।
- vii. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय कर देय होगा।
- viii. वार्षिक कोयला खनन योजना में वर्ष के दौरान सीबीएम प्रचालन के लिए खनन पट्टा हेतु मानित क्षेत्र के व्यौरे, प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम तथा सीबीएम के उत्पादन के लिए लक्ष्य शामिल होगा, और कोयला मंत्रालय (एमओसी) तथा पट्टाधारक के बीच किए गए समझौता ज्ञापन में इसे शामिल किया जाएगा।
- ix. सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां सीबीएम के लिए क्षेत्र की पहचान करेंगी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करेंगी। संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के 24 माह के भीतर, पट्टाधारक सूचना और रिकार्ड हेतु क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) डीजीएच को प्रस्तुत करेगा और इसकी सूचना कोयला मंत्रालय को दी जाएगी। इस प्रकार प्रस्तुत की एफडीपी को पट्टाधारक के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा।
- x. एमओपीएंडएनजी द्वारा पर्याप्त यथोचित कारणों के साथ तथा मामला-दर-मामला आधार पर एफडीपी प्रस्तुतिकरण की समयावधि को 12 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- xi. मूल्यांकन योजना और एफडीपी प्रस्तुतिकरण में 36 माह से अधिक का विलंब होने पर, पट्टाधारक को प्रति माह एक लाख रुपए का दंड देना होगा।
- xii. एफडीपी में अनुमानित तारीख से पहले पट्टाधारक उत्पादन शुरू नहीं करेगा। उत्पादन में विलंब होने की स्थिति में, पट्टाधारक को विलंब के प्रत्येक माह के लिए एक लाख रुपए का दंड देना होगा।
- xiii. सीबीएम दोहन के लिए सीबीएम प्रचालन का अनुभव रखने वाले केन्द्र अथवा राज्य सरकार के पीएसयूज की समान भागीदारी होगी और मुख्य शेयरधारिता पट्टाधारक की रहेगी। इससे पट्टाधारक द्वारा सीबीएम निष्कर्षण कार्य के लिए घेरलू अथवा विदेशी अनुभवी तकनीकी डिवेलपमेंट अथवा सेवा संविदाकारों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xiv. सीबीएम खनन पट्टा की अवधि तभी समाप्त होगी जब कोयला पट्टा की अवधि समाप्त होगी।
- xv. पट्टाधारक द्वारा कोयला खनन पट्टा के अंतर्गत आने वाले सीबीएम क्षेत्रों का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि कोयला खनन कार्यों से पहले सीबीएम का निष्कर्षण कार्य सहज ढंग से हो सके अथवा

कोयला खनन प्रचालनों के साथ साथ किया जाए ताकि सीबीएम का इष्टतम रूप से विकास और संरक्षण किया जा सके।

2. पट्टाधारक द्वारा संबंधित संविधियों के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण, सुरक्षा आदि से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2018

F. No. 19018/12/2015-ONG-I.—In partial modification of Coal Bed Methane (CBM) Policy Notification No.O-12011/1/97/ONG.DO.IV dated 19.07.1997 and in supersession of the notification no. 19018/12/2015-ONG-I dated 3rd November, 2015 the Government of India exercising the powers conferred under section (12) of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) hereby notifies the consolidated terms and conditions for grant of exploration and exploitation rights to Coal India Limited (CIL) and its subsidiaries from coal bearing areas for which they possess mining lease for coal, as hereunder:

- i. The right vested/mining lease with CIL and its subsidiaries for extraction of coal under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 or Coal Mines (Nationalization) Act or Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 or any other act so specified, would be deemed to be a mining lease granted under the PNG Rules 1959 for exploration and exploitation of CBM. CIL and its subsidiaries need not apply for separate grant of license/lease under the PNG Rules, 1959 for extraction of CBM, for such areas.
- ii. As a lease holder CIL and its subsidiaries will comply with the ORD Act 1948 and P&NG rules 1959 for CBM operations in all such blocks/ fields;
- iii. Lessee(s) would comply with existing policy of Government of India for utilization and pricing of natural gas.
- iv. Lessee(s) will be required to pay royalty and requisite fees, levies and taxes as applicable from time to time to State/Central Government at prevailing rates at par with payments which are required to be made for natural gas and as revised from time to time.
- v. CIL and its subsidiaries will, at present, require to pay royalty @ 10 % ad valorem sale value at the well head to concerned State Government, a fixed one time signature bonus equivalent to US\$ 0.3 Million in Indian Rupees on the date of signing of the CBM Contract and also Production Level Payment (PLP) on the CBM production @ 2.5% of the Sale Value of the CBM produced, to Central Government.
- vi. Exemption from payment of customs duty on imports under SI no. 404 of notification no. 50 /2017 –Customs dated 30th June, 2017, other relevant provisions therein and any

other notifications issued in this regard from time to time by the government will be applicable.

- vii. Income tax will be payable as per the income Tax Act, 1961.
 - viii. Annual coal mining plans will include details of the area deemed to be mining lease for CBM operation, committed work programme and target for production of CBM during the year, and the same will be incorporated in the MOU between Ministry of Coal (MOC) and the lessee.
 - ix. CIL and its subsidiaries will identify the area for CBM operation and sign the contract with the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Within 24 months of signing of contract, the lessee shall submit Field Development Plan (FDP) to DGH for information and record, under intimation to the MOC. FDP so submitted shall have the approval of the Board of the lessee.
 - x. The time period for submission of FDP may be extended by 12 months by MoP&NG on a case to case basis with sufficient justifications.
 - xi. For delay in submission of appraisal plan and FDP beyond 36 months, the lessee will be liable to pay a penalty of Rs. One lakh per month.
 - xii. The lessee shall start production not later than the projected date in the FDP. For delay in production; lessee would be liable to pay a penalty of Rs. One lakh per month of delay.
 - xiii. Equity participation for CBM exploitation shall be limited to Central or State PSUs with experience in CBM operations with the majority share holding remaining with the Lessee. This shall not restrict the engagement of experienced technical developers or service contractors, whether domestic or foreign, for CBM extraction by the Lessee.
 - xiv. Relinquishment of CBM mining lease will be co-terminus with coal lease.
 - xv. CBM areas covered under coal mining lease area will be utilized by the lessee in a manner so as to facilitate extraction of CBM prior to coal mining operations or simultaneously with coal mining operations to optimally develop and conserve CBM.
2. All statutory requirements relating to Environment, Safety, etc. shall be complied with by the Lessee in accordance with the provisions of the relevant statutes.

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.